फ़रीदाबाद में मज़ार के नाम पर अवैध दीवार गिराई, मंदिर को छुआ तक नहीं

शहर में एमसीएफ की जगह हिन्दू संगठनों ने सँभाली जिम्मेदारी

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबाद : बाटा चौक फ़्लाइओवर के ठीक नीचे 2 जुलाई को एक जगह को घेरकर खड़ी की गई तीन फुट ऊँची दीवार को बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यह कहकर गिरा दी कि यहाँ मज़ार बनाई जा रही थी। इस दीवार को गिराने के बाद इन लोगों ने इस जगह से दस कदम की दूरी पर बने मंदिर में जाकर मत्था टेका और वहाँ से जय श्रीराम के नारे लगाते हुए चले गए।

आस्था का अवैध निर्माण

बाटा चौक फ्लाईओवर के नीचे फड़ वालों का बाज़ार लगता है। यह बाज़ार नहीं बल्कि सैंकड़ों हिन्दू मुस्लिम परिवारों के भरण-पोषण का सहारा बना हुआ है। एनआईटी रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए इस बाज़ार के साथ ही सीढ़ियाँ भी बनी हैं। ट्रेनों की आवाजाही की वजह से यह फड़ बाज़ार खूब चलता है। इधर कोरोना की वजह से ट्रेनें बंद हुईं तो फड़ वालों का धंधा चौपट हो गया। लेकिन आसपास की झुग्गी बस्ती से लोग सस्ता सामान ख़रीदने की वजह से इस फड़ बाज़ार में आ जाते हैं।

जिस जगह पर बनी दीवार को मजार बताकर गिराया गया, वहाँ मौक़े पर कोई मज़ार नहीं है और न पहले से थी। वहाँ एक साफ़ सुथरा चबूतरा बना हुआ था जहां आते-जाते लोग नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन चूँकि बाटा फ़्लाइओवर की नीचे की यह जगह नगर निगम फ़रीदाबाद (एमसीएफ) की है तो यह चबूतरा और वो दीवार अवैध निर्माण ही है। जिसे गिराने का काम एमसीएफ का है लेकिन शहर की क़ानून व्यवस्था भी पुलिस के बजाय हिन्दू संगठनों ने संभाल रखी है तो ऐसी जगहों पर जाकर वे लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं।

वहाँ कपड़े की फड़ लगाने वाले जितेन्द्र ने बताया कि 2 जुलाई को दोपहर में क़रीब 50 लोगों की भीड़ जय श्रीराम के अलावा अन्य उत्तेजक नारे लगाते हुए आई और उस दीवार को गिराने लगे। वे उसे बार-बार मज़ार बता रहे थे लेकिन हम लोग पिछले बारह साल से वहाँ लोगों को नमाज़ पढ़ते ही देखते आए हैं। नमाज़ पढ़ने वाले भी ज़्यादातर ट्रेनों से आने-जाने वाले लोग होते थे जो यहाँ जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़कर दौड़कर ट्रेन पकड़ते थे। उस कथित मज़ार से दस कदम पर बने मंदिर के बारे में पूछने पर जितेंद्र ने बताया कि क़रीब पाँच साल पहले हम लोग ने आपस में चंदा करके यह मंदिर बनाया। इसमें हमारे आसपास के तमाम मुस्लिम दुकानदारों ने भी सहयोग किया था।

तो आख़िर दीवार गिराने वाले कौन थे, जितेंद्र के पड़ोसी दुकानदार विद्यासागर ने कहा कि हमारी मार्केट का एक भी दुकानदार उस भीड़ में शामिल नहीं था। सभी बाहरी लोग थे। ऐसा लगता है कि किसी ने मुखबिरी करके यह हरकत कराई है। अन्यथा इतने सालों से हम लोग यहाँ रोटी रोज़ी कमा रहे हैं, न नमाज़ पढ़ने वाले उस चबूतरे पर हम लोगों को कभी एतराज़ था और न मुस्लिम दुकानदारों को कभी पड़ोस के मंदिर पर एतराज था। जितेंद्र ने कहा कि देखा जाए तो दोनों धार्मिक निर्माण एमसीएफ की ज़मीन पर है। दोनों ही अवैध है। बाहरी लोग माहौल ख़राब करने आ जाते हैं। अब हम लोग कितनी ही सफ़ाई दें लेकिन मुस्लिम दुकानदार तो हमारे ऊपर ही शक करेंगे।

'हम लोग कुछ नहीं बोले'

टेलरिंग का काम करने वाले रजब अली ने बताया कि 2 जुलाई को जितने लोग आए थे, उससे ज़्यादा संख्या हमारी थी लेकिन हम इस मार्केट की बदनामी न हो, इसलिए चुप रहे। हमारे लड़के भी कसमसा रहे थे लेकिन हमने रोक दिया। हम विरोध करते तो मामला तूल पकड़ता और टकराव होता, हमारी मार्केट हमेशा के लिए बदनाम हो जाती।

यह पूछे जाने पर कि आख़िर यह जगह क्या है, मज़ार है कि मस्जिद है या क्या है? रजब अली ने कहा कि यह जगह न मस्जिद है और न मज़ार है। मस्जिद के लिए जो सबसे पहली शर्त है कि वह अवैध जगह पर नहीं बनाई जा सकती। वहाँ कोई न कोई इमाम या मौलाना होगा। इस जगह को आप ऐसे समझिए कि किसी भी जगह को साफ़ करके वहाँ नमाज़ पढ़ लेना, जैसे कई बार लोग चलती ट्रेन में समय होने पर पढ़ते हैं, प्लैटफ़ॉर्म पर पढ़ लेते हैं। जगह साफ़-सुथरा होना ही ऐसी जगहों पर नमाज़ के लिए पहली शर्त है। चबूतरा इसलिए बनाया गया था कि उसकी सफ़ाई में आसानी रहती है।

तो फिर दीवार क्यों बनाई गई, इसके जवाब में रजब अली के लड़के तौहीद ने कहा कि उस चबूतरे के चारों तरफ़ बहुत गंदगी है। लोग आसपास खड़े होकर पेशाब करते थे। इसलिए दीवार बनाई गई ताकि लोग चबूतरे तक नहीं पहुँचे। लेकिन इस संवाददाता ने जब यह कहा कि क़ब्ज़ा तो इसी तरह किया जाता है, रजब अली ने कहा कि हम लोग 2010 से यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं। चाहते तो अब तक यहाँ संगमरमर की मस्जिद खड़ी कर लेते। लेकिन जगह एमसीएफ की है, हम कैसे यहाँ मस्जिद बना सकते हैं? जब संवाददाता ने पड़ोस के मंदिर का पक्का निर्माण किए जाने के बारे में पूछा तो रजब अली ने कहा कि वो उनकी आस्था का मामला है लेकिन हम लोग इस्लाम के हिसाब से चलेंगे।

नगर निगम का साम्प्रदायिक नज़रिया

ऐसा नहीं कि एमसीएफ बाटा फ़्लाइओवर के नीचे लगने वाली इस मार्केट से अनजान है। नीलम पुल के नीचे जब कुछ दिनों पहले भीषण आग लगी थी तो पुल के नीचे अवैध क़ब्ज़ों का मामला गूंजा था। उसी समय एमसीएफ के कुछ अफ़सरों और कर्मचारियों ने इस मार्केट पर भी चढ़ाई की थी। उन्होंने पुल के नीचे फड़ और रेहड़ी लगाने वालों को अल्टीमेटम दिया कि वे फुटपाथ और रास्ते पर अपनी से दुकानें हटा लें, अन्यथा तोड़ दिया जाएगा। दुकानदारों ने एमसीएफ दफ़्तर पर इस आदेश के खिलाफ़ प्रदर्शन किया।

एमसीएफ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने और कुछ तो नहीं किया लेकिन जिस चबूतरे पर नमाज़ पढ़ी जाती थी, उसे आकर तोड़ दिया। सामान फेंक दिया। नमाज़ पढ़ने का चबूतरा तोड़े जाने के समय एमसीएफ के कुछ अधिकारियों ने साम्प्रदायिक टिप्पणियाँ भी कीं। इस कार्रवाई के दौरान दस कदम की दूरी पर बने मंदिर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इस मंदिर के पास बहुत सारे ऑटो खड़े रहते हैं। ऑटो चलाने वाले तीर्थ ने बताया कि जब एमसीएफ ने नमाज़ पढ़ने वाला चबूतरा तोड़ा तो हम लोग बहुत डर गए थे, क्योंकि हमें मंदिर टूटने का ख़तरा था। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मंदिर बच गया। यह पूछे जाने पर कि क्या उस चबूतरे से उन लोगों को कोई दिक्क़त है? तीरथ ने कहा, हमें क्यों एतराज होगा। हमारा क्या नुक्सान हो रहा उससे? वो अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, हम इस मंदिर में पूजा करते हैं। हमने एक ब्राह्मण पुजारी भी रखा हुआ है। पुजारी जी बिहार के रहने वाले हैं।

बहरहाल, नीलम पुल जब बन गया और चालू हो गया तो बाटा पुल के नीचे दुकानदारों ने भी राहत की साँस ली। उन्हें लगता है कि उजड़ने का ख़तरा टल गया है। इसके बाद मुस्लिम दुकानदारों ने वह चबूतरा फिर से बना लिया। इस बार तीन फुट की दीवार भी बना दी गई। इस चबूतरे पर जुमे की नमाज़ नहीं होती है लेकिन पाँच वक्त की नमाज़ के पाबंद लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं। 2 जुलाई को जब से हिन्दू संगठनों ने चबूतरे के पास बनी तीन फुट की दीवार गिराई है, उस दिन से यहाँ नमाज़ बंद है। हिन्दू संगठनों ने दीवार गिराते हुए कहा था कि अगर यहाँ नमाज़ हुई तो हम फिर आएँगे और नमाज़ नहीं होने देंगे। लोगों ने चादर लगाकर वो जगह घेर दी है।

बाइपास रोड पर तोड़ी गई थी मस्जिद

बदरपुर बॉर्डर से फरीदाबाद की तरफ़ आने वाली बाईपास रोड पर सेक्टर 29 के पास एक पुरानी मस्जिद को हूडा ने सड़क चौड़ी करने के नाम पर गिरा दिया था। इस बाईपास रोड को चौड़ा किया जाना है और अंत में इसे मुम्बई जाने वाले एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाना है।

इस रोड पर इस मस्जिद के अलावा कई मंदिर भी बने हुए हैं लेकिन हूडा ने एक भी मंदिर बाईपास रोड पर नहीं तोड़ा। इतना ही नहीं इसी रोड पर सेक्टर 10, 8, 9 के सामने बड़े बड़े शो रूम बने हुए हैं लेकिन हूडा ने इन शोरूमों पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा सड़क चौड़ा करने के नाम पर सैकड़ों पेड़ काट डाले गए। शहर के लोग इन पेड़ों को नहीं बचा सके।

तिकोना पार्क में गंदगी मंजूर, साफ नमाज़ी नहीं

एनआईटी इलाक़े के तिकोना पार्क में बीचोंबीच पार्क की एक ज़मीन ख़ाली पड़ी है। पार्क में एक पानी की टंकी है जो अब जर्जर हालत में है। इस पार्क में कुछ दलितों ने अस्थाई ठिकाना बना रखा है। तिकोना पार्क ऑटोमोबाइल मार्केट के दुकानदार यहाँ अपना कबाड़ फेंकते हैं। इसी मार्केट के मुस्लिम दुकानदारों और मैकेनिकों ने पार्क का एक कोना साफ़ कर यहाँ नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर वो लोग पिछले दस बारह साल से नमाज़ पढ़ रहे थे लेकिन कभी कोई पक्का निर्माण नहीं किया। जगह पर चूँकि अवैध क़ब्ज़ा है इसलिए मस्जिद बनाई नहीं जा सकती।

इस बुधवार को नगर निगम के दस्ते ने वो दरी वग़ैरह हटा दी जिस पर नमाज़ पढ़ी जाती थी। इस पर तिकोना पार्क के हिन्दू दुकानदारों ने नगर निगम वालों को काफ़ी खरी खोटी सुनाई। दुकानदारों ने कहा कि कम से कम इस पार्क को साफ कराकर निगम इसका रखरखाव क्यों नहीं करता। नमाज़ पढ़ने वालों ने तो वहाँ फिर भी जगह को साफ़ सुथरा कर रखा है। हालाँकि दुकानदारों ने स्वीकार किया कि यहाँ की गन्दगी के लिए वे लोग भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं।

दस घंटों में एसएन रॉय का आदेश वापस, गब्बर के कहने पर हटाए थे 37 डेपुटेशन वाले

फरीदाबाद और गुड़गांव नगर निगमों के 22 अधिकारी, कर्मचारी जमे रहेंगे मलाईदार पदों पर

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: हरियाणा के तमाम नगर निगमों में डेपुटेशन पर काम कर रहे 37 अफसरों और कर्मचारियों को एक ही आर्डर से एक ही दिन में उनके मूल विभाग में भेजने का निर्देश दिया गया लेकिन जैसे-जैसे शाम ढलती गई, ये आर्डर वापस ले लिया गया। इस आदेश से प्रभावित होने वाले अफसर और कर्मचारी मलाईदार पदों पर थे और पिछले कई साल से यहां जमे हुए थे। इस आदेश वापसी लेकर तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस मामले में कुछ न कुछ ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से इस आदेश को लेकर खट्टर सरकार की बदनामी हो रही है। इस आदेश से फरीदाबाद और गुड़गांव नगर निगम सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे।

5 जुलाई का आदेश 5 को ही वापस

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव एस.एन. रॉय ने राजस्व विभाग, बिजली बोर्ड, पंचायत विभाग और स्वास्थ्य विभाग से आए डेपुटेशन पर आए अफसरों का डेपुटेशन खत्म करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके मूल विभागों में भेजने का आदेश जारी किया था। इसमें फरीदाबाद नगर निगम (एमसीएफ) के 5 और गुड़गांव नगर निगम के 17 अफसर कर्मचारी शामिल थे। रोहतक समेत अन्य जिलों से एक-एक, दो-दो के ही नाम इस डेपुटेशन खत्म किए जाने वाली लिस्ट में थे। आदेश में निर्देश था कि दूसरे विभागों से आए इन अधिकारियों और कर्मचारियों से सारे काम फौरन वापस ले लिए जाएं।

आदेश जारी होते ही सबसे ज्यादा हलचल गुड़गांव में मची और थोड़ा बहुत अफरातफरी फरीदाबाद में भी रही। फौरन फोन लाइनें व्यस्त हो गईं और भारी मन से एस.एन. रॉय ने 5 जुलाई को ही देर रात इस आदेश को वापस लेने और अगले आदेश तक सभी का डेपुटेशन बरकरार रखने का निर्देश जारी कर दिया। अफसरों को जगा-जगाकर आदेश वापसी के बारे में जानकारी दी गई।

आदेश के पीछे गब्बर

हरियाणा सचिवालय के सूत्रों का कहना है कि खुद को गब्बर कहने वाले शहरी निकाय मंत्री अनिल विज को राज्यभर से शिकायतें मिल रही थीं कि दूसरे विभागों से डेपुटेशन पर आए अधिकारी और कर्मचारी नगर निगमों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गुड़गांव नगर निगम और एमसीएफ के इंजीनियरिंग विभागों में कार्यरत इंजीनियर भारी रिश्वत लेकर काम कर रहे हैं। शिकायत में गुड़गांव नगर निगम का जिक्र करते हुए कहा गया कि राज्य के आला अफसरों के रिश्तेदार होने की वजह से भी कई इंजीनियरों को तैनाती मिली है।

सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों अपने एक रिश्तेदार को गुड़गांव या मानेसर में लगाने का आग्रह का एक मंत्री ने अनिल विज से किया। विज ने उस मंत्री को मना कर दिया और बताया कि डेपुटेशन वाले बहुत बदनामी कर रहे हैं। विज ने उस मंत्री को तो मना कर दिया लेकिन यह भी दिखाना था कि वे डेपुटेशन वालों को हटा रहे हैं। विज ने इस संबंध में अतिरिक्त प्रधान सचिव एस.एन. रॉय को निर्देश दिया कि डेपुटेशन वालों को फौरन हटा दिया जाए। एस.एन. रॉय ने फौरन इस पर अमल किया और आदेश जारी कर दिया।

आदेश वापसी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। सचिवालय में जो अफवाह फैली, उसके मुताबिक गुड़गांव और फरीदाबाद नगर निगमों में डेपुटेशन पर काम कर रहे अफसरों और कर्मचारियों ने बहुत मोटे पैसे का आफर बिचौलियों को दिया और उन्होंने इस लिस्ट को रुकवाने के लिए पूरी सेटिंग की। इसमें एस.एन. रॉय के दफ्तर के कर्मचारियों से लेकर गब्बर के दफ्तर या उनके मुंह लगे दलालों की भूमिका से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी लिस्ट बिना रिश्वत लिए रोकी नहीं जा सकती। यह सौदा कम से कम दो से ढाई करोड़ की हैसियत रखता है। कितने पैसे पहुंचे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।

5 जुलाई को जब यह लिस्ट सचिवालय से बाहर निकली थी तो गब्बर के चमचों ने सबसे पहले इस लिस्ट को लेकर प्रचार शुरू किया था। उन्होंने उस दिन मीडिया को जानकारी दी थी कि गब्बर अब किसी के काबू नहीं आएगा। वो नगर निगमों से भ्रष्टाचारियों का सफाया कर देगा। लेकिन ऐसा प्रचार करने वाले उस दिन के बाद से मीडियाकर्मियों को दिखाई नहीं दे रहे हैं।

फरीदाबाद से कौन-कौन

डेपुटेशन पर नगर निगम फरीदाबाद में आए-सहायक इंजीनियर हकीमुद्दीन, चेतना दलाल सहायक जिला अटॉर्नी, राहुल दहिया सहायक जिला अटॉर्नी, देवेश गर्ग सहायक जिला अटॉर्नी, मोहम्मद वाजिद चपरासी शामिल हैं।

गुड़गांव से कौन-कौन

डेपुटेशन पर गुड़गांव नगर निगम में आए - हरिओम अत्री राजस्व अधिकारी, रमन यादव कार्यकारी अभियंता, अमित संदलिया कार्यकारी अभियंता, कुलदीप सिंह सहायक अभियंता, अजय शर्मा सहायक अभियंता, विनोद कुमार सहायक, जिले सिंह सहायक, मंजीत सिंह सहायक, शीतल दास सहायक, समीर श्रीवास्तव जोनल कराधान अधिकारी, बालेराम क्लर्क, कमल क्लर्क, संजय क्लर्क, अजमेर सिंह ड्राइवर, रिषी कपूर ड्राइवर, हरिश्चंद्र चपरासी, सूरज प्रकाश चपरासी शामिल हैं।